

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 449

दिनांक 05.12.2023/ 14 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

सीमावर्ती गांवों का विकास

1449 श्री प्रताप राव जाधव:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री सुधीर गुप्ता:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के सीमावर्ती गांवों को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने सीमाओं पर स्थित सभी गांवों की पहचान कर ली है और यदि हां, तो गांवों के नामों सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश के सीमावर्ती गांवों में पर्याप्त अवसंरचनात्मक, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं सृजित करने के लिए सरकार द्वारा आबंटित और जारी किए गए बजट का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने देश के सीमावर्ती गांवों में किए जाने वाले अवसंरचनात्मक और विकासात्मक कार्यों के लिए कोई नोडल एजेंसी गठित की है/नियुक्त की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री निशिथ प्रामाणिक)

(क) से (ग) : सीमावर्ती गांवों का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है। इस उद्देश्य से, वर्ष 1986 से सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) चलाया जा रहा है। बी.ए.डी.पी. के अंतर्गत अन्तराष्ट्रीय सीमा पर स्थित प्रथम वासस्थान से 0-10 किलोमीटर (एरियल दूरी) के अन्दर स्थित सभी

जनगणना गाँव/शहर, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्र सम्मिलित हैं, जिनको राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा चिन्हित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, सीमावर्ती गावों में विकास सम्बन्धी कमियों को दूर करने हेतु, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 प्रखंडों के चिन्हित गावों के लिए वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम (वी.वी.पी.) को अनुमोदन प्रदान किया है। वी.वी.पी. के अंतर्गत, प्राथमिकता के आधार पर 662 गावों को चिन्हित किया गया है। सम्बंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के जिलों और प्रखंडों, जिनके गाँव वी.वी.पी. के अंतर्गत सम्मिलित किये गए हैं, का विवरण अनुलग्नक-1 पर उपलब्ध है। गाँवों को विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के बाद चिन्हित किया गया है।

(घ) से (ड): केन्द्र प्रायोजित योजनाओं, नामतः, बी.ए.डी.पी. और वी.वी.पी. के अंतर्गत सीमावर्ती गावों में विकासात्मक कार्यों का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन करते हैं। वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सीमावर्ती गावों में ढांचागत सुविधाओं का सृजन और विकास कार्यों का कार्यान्वयन करने के लिए बी.ए.डी.पी. के अन्तर्गत 600.00 करोड़ रुपये और वी.वी.पी. के अन्तर्गत 150.00 करोड़ रुपये (भारत की आकस्मिकता निधि से) का बजट आवंटित किया गया है। निधि जारी करना एक सतत प्रक्रिया है, जो कि समय-समय पर स्वीकृत परियोजनाओं, उनकी प्रगति और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुमानित मांगों पर आधारित है।

\*\*\*\*\*

